चावल विकास हेतु एकीकृत योजना

3351. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 105 करोड़ रुपए की लागत से चावल विकास के लिए एक एकीकृत योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस योजना के अधीन 79.50 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार और शेष राशि राज्य सरकार व्यय करेगी ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में उपर्युक्त योजना को कार्यान्वित किया जा चुका है ;

(घ) क्या इस संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु उन राज्यों में जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया गया हैं ;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस तरह के शिविर आयोजित किए गए थे और राज्य-वार उनकी संख्या कितनी-कितनी थी और कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(च) क्या सरकार ने प्रशिक्षण देने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए लाभों का कोई मूल्यांकन किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित समेकित चावल विकास कार्यक्रम एक सतत योजना है। 1993-94 के लिए भारत सरकार ने 79.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यों में इस योजना के कार्यान्वियन के लिए 103.65 करोड़ रुपए का एक परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें से 78.49 करोड़ रुपए का अंश केन्द्र का है तथा राज्यों को अपने हिस्से के 25.16 करोड़ रुपए का अंशदान देना है।

(ग) यह योजना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिल नाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) से (च) जी, हां। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविरों की संख्या तथा उनमें भाग लेने वाले किसानों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये) समेकित चावल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन से, जिसमें किसानों का प्रशिक्षण शामिल है, उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण और चावल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

विवरण

समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93 में आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविरों तथा उनमें भाग लेने वाले किसानों की संख्या

क्र०सं०	राज्य का नाम	आबंटित प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	प्रायोजित प्रशिक्षण शिविरों की संख्या	किसानों की संख्या (लक्ष्य)	भाग लेने वाले किसानों की संख्या
1.	असम	43	—	4300	—
2.	बिहार	85	सू० न०	8500	सू० न०
3.	मध्य प्रदेश	85	19	8500	1900 जनवरी 93 तक
4.	उड़ीसा	78	सू० न०	7800	सू० न०
5.	उत्तर प्रदेश	58	46	5800	1600
6.	पश्चिम बंगाल	40	40	4000	4000
7.	त्रिपुरा	5	1	500	100
8.	आंध्र प्रदेश	2	सू० न०	200	30513
9.	गुजरात	4	1	400	100
10.	महाराष्ट्र	9	सू० न०	900	सू० न०
11.	अरूणाचल प्रदेश	2	सू० न०	200	सू० न०
12.	मेघालय	2	सू० न०	200	सू० न०
13.	नागालैण्ड	2	सू० न०	200	सू० न०

सू० न०—राज्य द्वारा सूचित नहीं ।

Farmers Welfare Fund

3352. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to organise a full fledged Farmers Welfare Fund for the benefit of farmers all over the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, what steps proposed to be taken to create a nation-wise body to look after the welfare of farmers; and

(d) whether Government propose to consider establishing a Pension Fund for Farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal to create a nation-wide body to look after the welfare of farmers.